वर्ष-9//अंक-8//मई 2022
ISSN 2454–5805
₹20/-

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

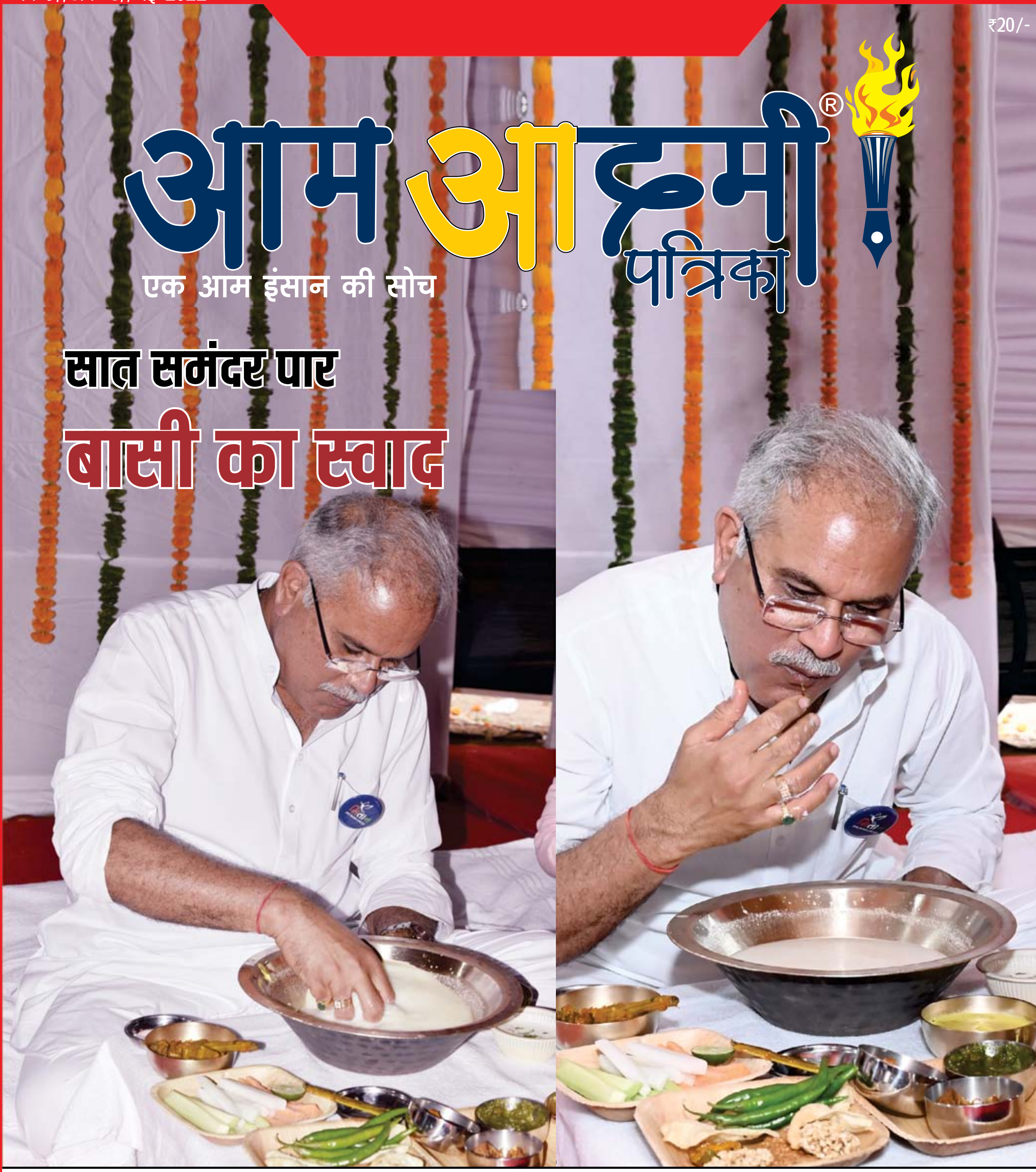

सात समंदर पार
बासी का स्वाद

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

» 8

भूमिहीन मजदूरों को 7000 रु. टूरिज्म के होटलों में बार की मंजूरी

» 16

छत्तीसगढ़ में खुलेगा ग्रामीण उद्योग पार्क

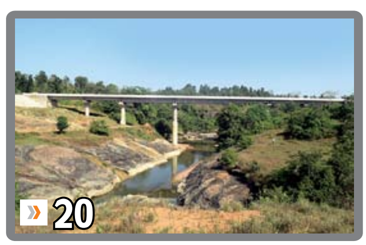

» 20

विकास पथ पर तेजी से बढ़ता कदम

www.aamaadmi.in

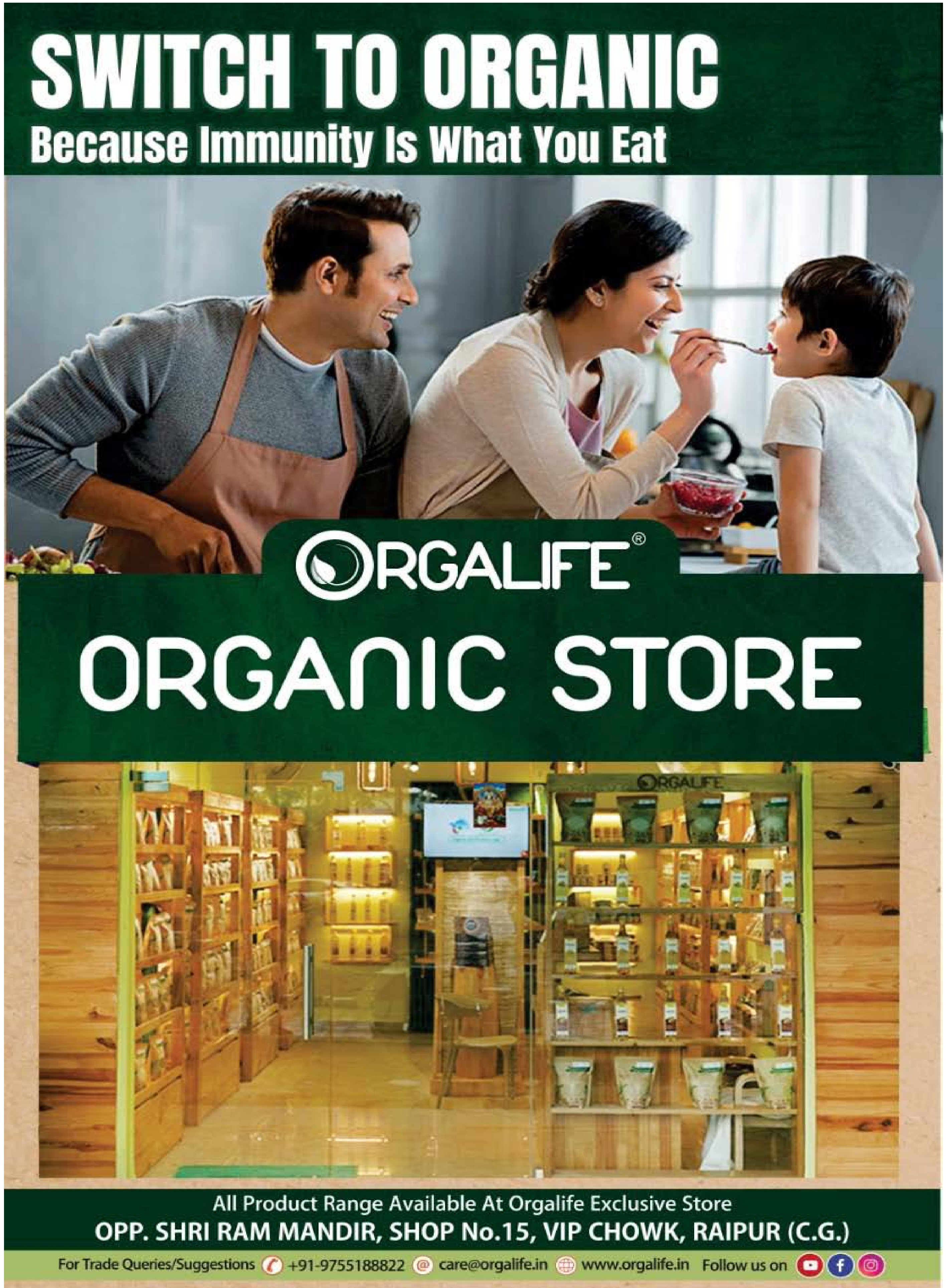

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-9//अंक-8//मई 2022

प्रबंध संपादक	: उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	: प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	: नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	: प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	: देवेन्द्र देवांगन
मैग्जीन डिज़ाइनर	: युनिक ग्राफिक्स
मार्केटिंग मैनेजर	: किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	: निरूपमा मिश्रा
अकाउंट असिस्टेंट	: प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	: योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन : 0771-4044047
ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम.
रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर
(छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

मई 2022

इस अंक में

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भाभा अटामिक रिसर्च सेन्टर ट्राम्बे-मुम्बई के सहयोग से विकसित सुगंधित धान की नवीन म्यूटेन्ट किस्में अब किसानों के खेतों में भी महकेंगी। 5

टैक्स वसूलने वालों को मिलेगा इनाम 10

परिवहन विभाग ने 1373.91 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया

50 लाख हे. में खरीफ फसलों की बुआई 12

बीते खरीफ से धान का रकबा 5 लाख 35 हजार हे. कम करने का लक्ष्य

कृषि से उद्योग की राहें 18

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उद्योगों से जोड़ने की पहल नई उद्योग नीति में

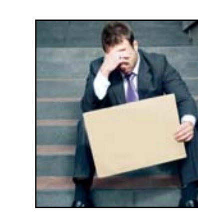

देश में बेरोजगारी दर बढ़ी 23

देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% हो गई

अब आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री 24

सीएम भूपेश बघेल का तूफानी दौरा शुरू हो चुका है।

यूक्रेन को हथियारों देगा जर्मनी 28

जर्मनी यूक्रेन को 50 गेपर्ड टैंक सप्लाई करने के लिए तैयार

सरकार का फीडबैक जरूरी

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

अगले साल ही छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले है और सरकार के कामकाज का फीडबैक जनता से लेना जरुरी है। तभी तो पता चलेगा कि अगली बार सफलता के कितने करीब है। चलिए हम बात कर रहे है भूपेश सरकार के भेंट-मुलाकात की। सजग मुख्यमंत्री हर साल जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करता है। इसके लिए वह जनता के बीच जाता है। अधिकारियों की बैठकों से जानने की कोशिश करता है कि सरकारी योजनाओं पर ठीक से अमल हो रहा है या नहीं। अधिकारी झूठ भी बोल सकते हैं फर्जी आंकड़े भी पेश कर सकते हैं, इसलिए सजग मुखिया अधिकारियों पर भरोसा नहीं करता है, वह जनता से गांवों में जाकर पूछता है कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, जनता सरकार से क्या चाहती हैं, जनता के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सजग व संवेदनशील सीएम हैं। उन्हें हकीकत पसंद है, इसलिए जब भी लोगों के बीच जाने का मौका मिलता है तो वह जरूर सरकार, अधिकारियों, विधायकों के परफारमेंस के बारे में जरूर पूछते हैं। वह जानते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री के अच्छा होने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए वह हर स्तर पर जाकर हकीकत का पता लगाते हैं और कमी खामी को दूर अगला चुनाव जीतने की संभावना को बढ़ाते हैं। इस बार वह चार मई से फिर छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वह अधिकारियों की बैठक लेंगे, चार गांवों के लोगों से रोज मिलेंगे। जनता से अधिकारियों व विधायक की परफारमेंस की जानकारी लैंगे। ताकि उन्हें पता रहे कि जमीनी हकीकत क्या है, कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने के रास्ते में कोई बाधा तो नहीं है। किसी भी सरकार की सत्ता में वापसी की राह में सबसे बड़ी बाधा सरकार विरोधी भावना होती है। सरकार, विधायकों के प्रति असंतोष की भावना होती है। चुनाव में पार्टी की जीत के लिए जरूरी है जानना कि विधायक को जनता कितना पसंद करती है, उसे दोबारा चुनना चाहती है या नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह सब जानने का प्रयास करेंगे। उसी के आधार पर सरकार की वापसी की पुख्ता योजना बन सकेंगी। सीएम ने विधायकों के परफारमेंस को लेकर कई बार सर्वे करा चुके हैं। माना जा रहा है कि 30-40 विधायकों का परफारमेंस चुनाव जिताने वाला नहीं है। इस बार कम से कम 30-40 विधायक बदले जाएंगे। ताकि कांग्रेस की जीतने की संभावना को बढ़ाया जा सके। विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा समय है, इसलिए सभी विधायकों को आशवस्त करना जरूरी है कि उनकी टिकट नहं कट रही है, इसलिए भूपेश बघेल ने सभी विधायकों को आश्वस्त कर रखा है कि उनकी टिकट नहीं कट रही है। जिसकी टिकट कटनी है तो वह तो चुनाव के समय ही पता चलेगा ताकि वह पार्टी व सरकार को नुकसान न पहुंचा सके। पिछली बार सरकार बनाने में सरगुजा व बस्तर संभाग की अहम भूमिका रही है इसलिए भूपेश बघेल ने अपने दौरे की शुरूआत सरगुजा से की है ताकि पता लगाया जा सके, कांग्रेस के मजबूत गढ़ की स्थिति क्या है। गढ़ पहले से मजबूत हुआ है या नहीं। भूपेश बघेल एक चुनाव पार्टी को जिताकर संतुष्ट होने वाले नेता नहीं है,इसलिए वह दूसरा चुनाव जीतने के लिए जो कुछ जरूरी है, वह कर रहे हैं। उनकी तैयारिया के मुकाबले भाजपा की तैयारी कुछ खास नहीं है। भाजपा को जनता की नाराजगी की उम्मीद है।भूपेश बघेल हर स्तर भाजपा से बहुत आगे हैं, वह जानते हैं कि पार्टी चुनाव जीत सकती है लेकिन फिर भी वह सजग हैं। हर स्तर पर खुद सब चेक कर रहे है ताकि कहीं कोई कमी या खामी न रह जाए। और उसी वजह से पार्टी की सीटें कम हो जाएं। कांग्रेस को कम सीटें मिलें लेकिन जीत पक्की होनी चाहिए। जैसी यूपी में योगी की वापसी हुई है। वैसे ही भूपेश बघेल भी अच्छी वापसी चाहते हैं।

खेतों में बिखरेगी म्यूटेंट सुगंधित धान की महक

“इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भाभा अटामिक रिसर्च सेन्टर ट्राम्बे-मुम्बई के सहयोग से विकसित सुगंधित धान की नवीन म्यूटेन्ट किस्में अब किसानों के खेतों में भी महकेंगी। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सुगंधित धान की पांच नवीन म्यूटेन्ट किस्मों- ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेन्ट-1, विक्रम टीसीआर, छत्तीसगढ़ जवांफूल म्यूटेन्ट, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेन्ट तथा ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी के बीज प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को वितरित किए।”

कृषि उत्पादन आयुक्त ने किसानों से आव्हान किया कि वे सुगंधित धान के उत्पादन के लिए आगे आएं, राज्य सरकार सुगंधित धान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हरसंभव मदद करेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में धान की हजारों परंपरागत किस्में पाई जाती है जो अपनी सुगंध, औषधीय गुणों तथा अन्य विशिष्ट गुणों के लिए मशहूर हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की ऐसी 23 हजार 250 परंपरागत किस्मों के जनन द्रव्य का संग्रहण किया गया है। धान की परंपरागत सुगंधित किस्मों की दीर्घ अवधि, अधिक ऊंचाई तथा कम उपज की वजह से धीरे-धीरे किसानों ने इनकी खेती करना कम कर दिया है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा भाभा अटॉमिक रिसर्च सेन्टर मुम्बई के सहयोग से म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा सुगंधित धान की परंपरागत किस्मों की अवधि और ऊंचाई कम करने तथा उपज बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीछले 7 वर्षों से संचालित इस परियोजना के तहत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। परमाणु विकरण तकनीक के द्वारा प्रदेश की परंपरागत किस्मों- दुबराज, सफरी-17, विष्णुभोग, जवांफूल और सोनागाठी की नवीन म्यूटेन्ट किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिनकी अवधि और ऊंचाई में उल्लेखनीय कमी तथा उपज में आशातीत वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही धान की अन्य परंपरागत किस्मों के म्यूटेन्ट विकसित कर लिए जाएंगे। डॉ. चंदेल ने कहा कि अनुसंधान स्तर पर इन प्रजातियों के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं और अब इनके लोकव्यापीकरण हेतु किसानों के खेतों पर उत्पादन किया जा रहा है।

कैबिनेट फैसला...

भूमिहीन मजदूरों को 7000 रुपए टूरिज्म के होटलों में बार की मंजूरी

> छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के हित में कई अहम फैसले लिए है। मंत्री परिषद की मीटिंग में टूरिज्म बोर्ड के इकाईयों को बार लाइसेंस दिए जाएंगे। साथ ही पुरानी पेंशन योजना के बहाली के निर्णय पर मुहर लग गई है।

- एक नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया।
- प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्टों जिसमें 75 लाख रुपए बाजार मूल्य तक आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स में रजिस्ट्री शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट की प्रभावशीलता अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को जिनका आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना-2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 32 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहायक मानचित्रकर के 125 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची का एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी गई।

- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वनांचल उद्योग की स्थापना हेतु रियायत के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) की कंडिका 3.11 शेडों/फ्लैटेड फैक्ट्रियों (बहु मंजिला भवन के शेड) का भाड़ाक्रय पद्वति के अंतर्गत आबंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- संचालनालय आयुष के अंतर्गत स्टेनो टायपिस्ट के रिक्त पद की पूर्ति हेतु परीक्षा परिणाम की वैद्यता अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहायक वर्ग-तीन के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु पदोन्नति का कोटा एक बार 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन तथा राजीव मितान क्लब योजना लागू की गई है। इनके वित्तीय पोषण और क्रियान्वयन हेतु सभी प्रकार के विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष से अधिक की कालावधि के पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की राशि पर कुल 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अध्यादेश-2022 का अनुमोदन किया गया।

- आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क से छूट देने के संबंध में बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क के युक्तियुक्तकरण संबंधी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता का एक अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

- छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जल संसाधन विभाग में डिप्लोमा/डिग्रीधारी अमीनों को विभाग में रिक्त उप अभियंताओं (सिविल/वि./यां) के पदों पर नियुक्त करने हेतु विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाईयों के लिए रियायती दर पर होटल बार लायसेंस प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।
- स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाईयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया।
- नगर पालिक निगमों के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 426 बी के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- नगर पालिका और नगर पंचायत के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 345 के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- नगर पालिक निगम रायपुर की स्वामित्व के ग्राम डुमरतराई स्थित भूखण्ड का विक्रय फ्री-होल्ड के रूप में करने हेतु क्रियान्वयन की शक्तियां कलेक्टर रायपुर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- नगरीय निकायों के स्वयं के आधिपत्य या स्वामित्व के लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय या व्यवसायिक भवनों, फ्लैट्स, भू-खण्डों, परिसर और दुकानों का संबंधित नगरीय निकाय को राजस्व विभाग से विधिवत भू-स्वामित्व प्राप्त होने पर शर्तों के अधीन फ्री-होल्ड के रूप में संपरिवर्तन किया जाने का अनुमोदन किया गया।
- आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

- मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले वर्मी कम्पोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थो के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महा अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। माटी पूजन का कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की परंपरा अनुसार पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुक्रम में दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किए जाने एवं नवीन मार्गो के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आवश्यक शक्कर वितरण हेतु सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समकक्ष छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक अतिरिक्त खाद्यान्न एवं मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम-2010 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न विभागों निगम, मण्डल, कंपनी, बोर्ड के अधीन शासकीय भूमि पर निर्मित जर्जर शासकीय परिसर के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग हेतु रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ के अंकित वर्ल्ड फोर्बेस अंडर 30 में नॉमिनेट

इन सूरमाओ से लेंगे कड़ी टक्कर !!!

फोर्बेस मैगजीन दुनिया का सबसे बड़ा और जाना माना मैगजीन है। हर साल फोर्बेस अपनी लिस्ट निकालता है जिसमे सबसे धनी व्यक्तियों का नाम होता है, जिसके साथ युवाओ को प्रेरणा देने के लिए जिनकी उम्र 30 से कम है उनकी भी सूचि जारी करते है। ये 30 युवा दुनिया भर से होते है जिन्होंने दुनिया में कुछ नया लाया हो और इनकी संपत्ति भी ज्यादा हो। फोर्बेस अपने मैट्रिक्स में इन्वेंशन को तवज्जू देते है।

अंकित का नाम वर्ल्ड फोर्बेस अंडर 30 में नॉमिनेट

पेशे से वेल्थ मैनेजर (USA) अंकित यादव इस बार भारत का प्रतिनिधित्व फोर्बेस वर्ल्ड अंडर 30 में नॉमिनेटेड है दुनिया में इन इक्वलिटी घटाने की शोध और पहली बार शेयर मार्किट में इन्ट्रिंसिक वैल्यू के फार्मूला की खोज करने के कारण उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है।

अंकित कैसे पहुंचे फोर्बेस अंडर 30 तक

अंकित शेयर बाजार में भविष्यवाणी के लिए मसहूर है, शेयर मार्किट के पंडितो का मानना है की उनकी की गयी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होती अंकित के खरीदे शेयर आज मल्टीबैगर बन चुके है और देश में धूम मचा रहे है। अंकित ने साल 2021 में अपनी वेबसाइट लांच की जिसमे उन्होंने दुनिया में पहली बार इन्ट्रिंसिक वैल्यू के फामूर्ला की रचना की और निवेशकों ने इसे खूब सराहा। एक ही महीने में अंकित ने 1०5 करोड़ का कारोबार किया और देश में सनसनी मचा दीए इसके साथ ही अंकित 2021 से दुनिया में इन इक्वलिटी कैसे काम किया जाये इसपे शोध कर रहे है। इन वजहों से छोटे से शहर के अंकित आज दुनिया में और फोर्बेस में बड़ा नाम बना चुके है।

कोन है अंकित यादव

भिलाई के स्कूल से निकले, छत्तीशगढ़ में रहने वाले अंकित ने 18 की उम्र में शेयर बाजार में कदम रखा 2020 कोरोना काल में बूम के बाद उनके शेयर्स में भरी उछाल आया।

आज अंकित (USA) के जाने माने वेल्थ मैनेजर है और मार्किट मैस्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक है। उनके चाहने वालो की लम्बी कतार है और वो उन्हें शेयर मार्किट का बिग बुल तो कोई उन्हें अगला वारेन बफेट कहते है।

जल्दी जारी होगी सूचि

वर्ल्ड फोर्बेस जल्दी सूचि जारी करेगा और देश की निगाहे इस वेल्थ मैनेजर पर तिकी हुई होगी। माना जा रहा है की अगले महीने जारी हो सकती है यह सूचि इन इक्वलिटी गैप को कम करने की शोध करने वाले अंकित इस बार कुछ बड़ा धमाका कर सकते है।

टैक्स डिफाल्टर वाहन स्वामियों के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत वाहनों की कुर्की की होगी कार्रवाई

एकमुश्त निपटान योजना तहत 7 महीने में 2 हजार 135 वाहनों से 20.50 करोड़ रुपए बकाया कर की वसूली

परिवहन विभाग ने 1373.91 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व प्राप्ति में 19.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

टैक्स वसूलने वालों को मिलेगा इनाम

जिलों के ऐसे परिवहन अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने टैक्स संग्रहण में उल्लेखनीय कार्य किया है, उन्हें परिवहन आयुक्त के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशन में परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त के लगातार मार्गदर्शन से मुख्यालय एवं जिलों के परिवहन अधिकारियों एवं प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा लगातार प्रयास एवं मेहनत से राजस्व की प्राप्ति की जा रही है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व नुकसान को रोकने के लिए टैक्स डिफाल्टर की सूची जिलों के परिवहन अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी कर तथा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। यदि उसके बाद भी टेक्स डिफाल्टर वाहन स्वामियों द्वारा टैक्स जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जाती है, तो उन टैक्स डिफाल्टर वाहन स्वामियों के विरूद्ध ह्यभू-राजस्व संहिताह्य के तहत वाहनों के कुर्की की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि वाहन मालिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा वर्ष 2021-22 में ह्यएकमुश्त निपटानह्य योजना 13 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू की गई थी। जिसके तहत 2 हजार 135 वाहनों से 20.50 करोड़ रुपए बकाया कर की वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त शेष 2 हजार 37 वाहनों को जप्त किया गया है, जिसकी वसूली शेष है।

16 परिवहन चेकपोस्ट और 7 परिवहन उड़नदस्ता का संचालन

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा ओव्हरलोड मालयान वाहनों और विविध अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा 16 परिवहन चेकपोस्ट और 7 परिवहन उड़नदस्ता का संचालन किया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 1373.91 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। जिसमें शुल्क 196.64 करोड़ रुपये, समझौता-शुल्क/फाईन से 193.61 करोड़ रुपए, टैक्स-जीवनकालकर, मासिक कर और त्रै-मासिक कर से 983.66 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। इसी तरह वर्ष 2020-21 में इन मदों से 1147.92 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। जिसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1373.91 करोड रुपए राजस्व अर्जित करते हुए 19.69 प्रतिशत वृद्धि के साथ 225.99 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया गया। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन चेकपोस्ट एवं परिवहन उड़नदस्तों द्वारा 3 लाख 16 हजार 249 वाहनों से 71.06 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया। वही वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख 26 हजार 605 ओव्हरलोड मालयान वाहनों तथा विविध अपराधों के तहत चालानी कार्यवाही कर 165.60 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया।

टैक्स बकाया पर वाहनों की जब्ती

राज्य में कई पुराने मासिक, त्रै-मासिक कर बकाया है। जिलों के परिवहन अधिकारियों द्वारा वर्ष 2021-22 में 480 वाहनों से 22.04 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त 12 मार्च 2022 से 31मार्च 2022 तक अभियान चलाकर 588 वाहनों से 3.55 करोड़ रुपए बकाया टैक्स वसूल किया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जायसवाल, एनईसीओ, एसकेएस, सार्थक इस्पात, गोदावरी इस्पात, हाइटेक यार्ड, शारदा एनर्जी सिलतरा सहित कई कम्पनियों और फैक्ट्रियों में टैक्स जमा नहीं करने वाली वाहनों को जब्त किया गया है। इन वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग का लगभग 50 लाख रुपए बकाया है। इसी तरह विभिन्न फायनेंस कम्पनियों की 78 वाहनें जप्त कर खड़ी की गई है। इसके अतिरिक्त यार्डो में खड़ी गाड़ियों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यार्डों में खड़ी जब्त वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए फायनेंस कम्पनियों को

नोटिस जारी किया गया है। ऐसी वाहनें भी शामिल है, जिन्हें फायनेंसरों ने किश्त अदा नहीं कर अपने यार्डों में खड़ी कर दी थी। विभाग द्वारा बिना परमिट के यात्री वाहनों के संचालन करने वाली 763 वाहनों से 6 लाख 32 हजार 7 सौ रुपए वसूल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बिना परमिट 6 यात्री वाहनों को जप्त करने की कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन अमलों द्वारा ऐसी वाहनें जो बिना टैक्स जमा कर संचालित हो रही है, इन 4 हजार 259 वाहनों में निरन्तर कार्यवाही करते हुए 27.87 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया है, शेष 1037 वाहनों को जप्त किया गया है, इनकी वसूली शेष है।

50 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई

बीते खरीफ से धान का रकबा 5 लाख 35 हजार हेक्टेयर कम करने का लक्ष्य

कोदो, कुटकी और रागी के रकबे में 66 हजार हेक्टेयर की होगी बढ़ोत्तरी

दलहन-तिलहन एवं अन्य फसलों के रकबों में पौने तीन लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य

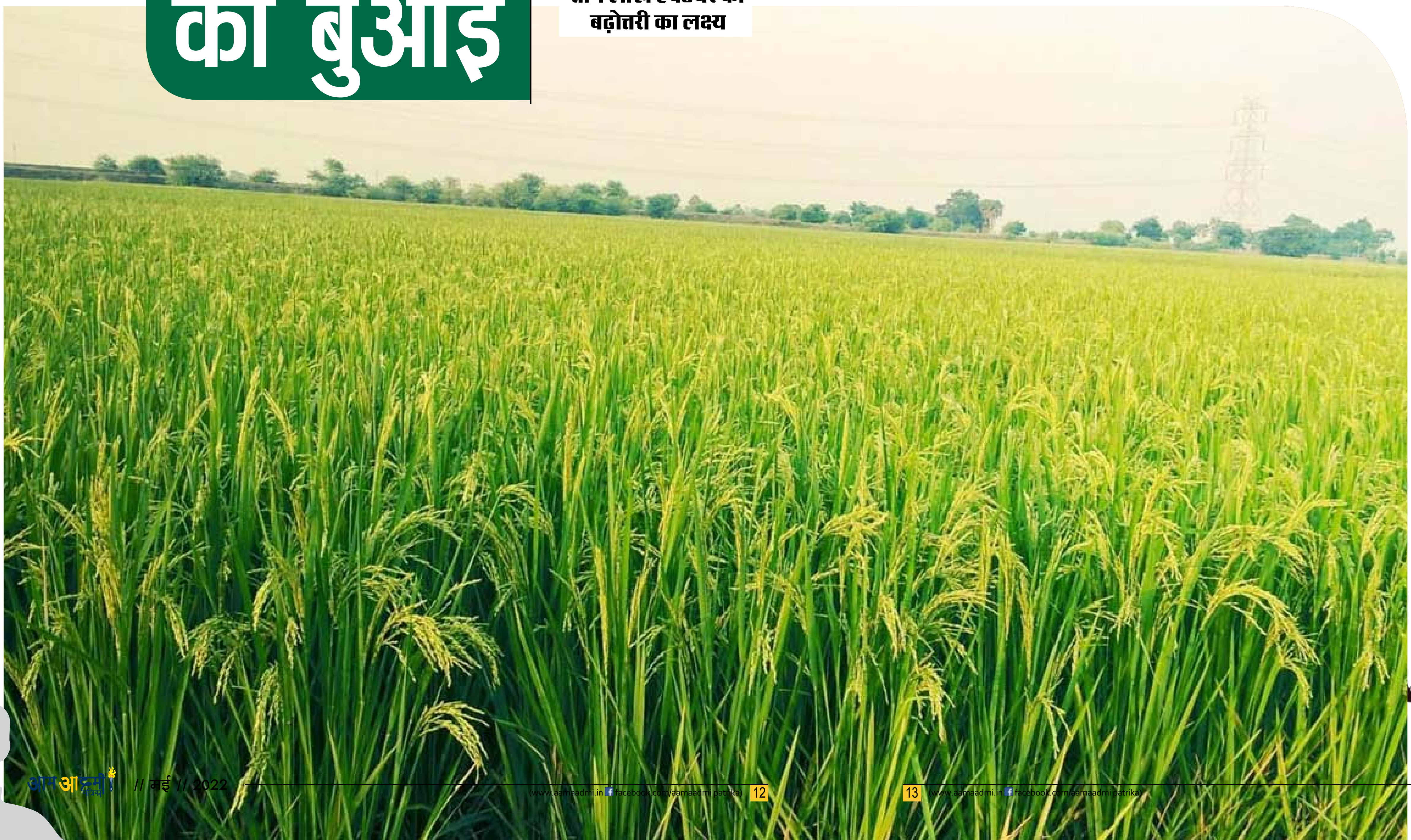

> खरीफ सीजन में फसलों की बुआई को लेकर लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है। खरीफ सीजन 2022 में कुल 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार फसलों की बुआई होगी, जो कि बीते खरीफ सीजन 2021 की तुलना में लगभग 55 हजार हेक्टेयर अधिक है।

खरीफ सीजन 2022 के बुआई लक्ष्य निर्धारण में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि धान के रकबे में बीते खरीफ सीजन के तुलना में 5 लाख 35 हजार हेक्टेयर की कमी कर दी गई है, जबकि मक्का के रकबे में लगभग एक लाख हेक्टेयर तथा कोदो, कुटकी और रागी के रकबे में लगभग 66 हजार हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की गई है। धान के रकबे को घटाने के साथ ही कृषि विभाग ने दलहन-तिलहन एवं अन्य फसलों के बुआई रकबे में बीत साल की तुलना में लगभग पौने तीन लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा है।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2021 में राज्य में 47 हजार 65 हजार 190 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। खरीफ सीजन 2022 में इस लक्ष्य को लगभग 55 हजार हेक्टेयर बढ़ाकर 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर कर दिया गया है। बीते खरीफ सीजन में राज्य में 38 लाख 99 हजार 340 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई थी, खरीफ सीजन 2022में इस लक्ष्य को घटाकर 33 लाख 64 हजार 500 हेक्टेयर कर दिया गया है। यानि धान के रकबे में 5 लाख 35 हजार हेक्टेयर की कमी लाने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। खरीफ सीजन 2022 में मक्का की बुआई 3 लाख 14 हजार हेक्टेयर में होगी, जबकि बीते वर्ष राज्य में 2 लाख 5 हजार हेक्टेयर में मक्का लगाया गया है। कोदो कुटकी और रागी का रकबा भी 82 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर एक लाख 47 हजार हेक्टेयर किया गया है। इस प्रकार राज्य में मोटे अनाज का रकबा भी 2 लाख 88 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 4 लाख 60 हजार हेक्टेयर किया गया है। दलहनी फसलों का रकबा 4 लाख 48 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जबकि बीते खरीफ सीजन में 2 लाख 77 हजार हेक्टेयर में दलहनी फसलों की खेती की गई थी। इसी तरह तिलहनी फसलों के रकबे में एक लाख की बढ़ोत्तरी करते हुए इनका रकबा दो लाख 67 हजार 700 हेक्टेयर कर दिया गया है। खरीफ 2021 में राज्य में एक लाख 66 हजार 670 हेक्टेयर में तिलहनी फसलें लगाई गई थी, अन्य खरीफ फसलों के रकबे में लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की गई है। खरीफ 2022 में अन्य खरीफ फसलें दो लाख 83 हजार हेक्टेयर में लगाए जाने का लक्ष्य है, जबकि बीते खरीफ सीजन में इनकी बोनी का रकबा एक लाख 33 हजार हेक्टेयर था।

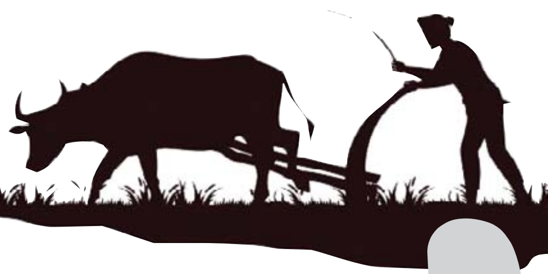

बड़े बुजुर्गों सहित युवाओं ने मुख्यमंत्री के आव्हान पर बोरे बासी खाकर दिया श्रम को सम्मान

प्रशासनिक अधिकारियों ने चाव से खाया बोरे बासी

सात समंदर पार बासी का स्वाद

> छत्तीसगढ़ सरकार के बोरे-बासी दिवस के मौके पर सात-समंदर पार भी स्वाद चखने का अवसर लोगों को मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रमिकों के साथ बैठकर बोरे बासी का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग लगातार बोरे बासी के बारे में जानकारी जुटा रहे थे और अधिकांश लोगों ने बोरे बासी खाया भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छत्तीसगढ़ी व्यंजन की इस तरह की प्रसिद्धि से गर्व महसूस कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग मजदूरों के लिए श्रमिक सियान सहायता योजना में एकमुश्त 10 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महिला स्वावलंबियों को आगे बढ़ाने के लिए ई रिक्शा में अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा ने की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नोनी सशक्तीकरण योजना में 18 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने एक मई को शुरू की गयी मितान योजना के बारे में भी घोषणा की है कि दूसरे चरण में ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। श्रम मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने कहा कि श्रमिकों के बिना निर्माण कार्य संभव नहीं है। उन्होंने श्रमिकों को राज्य के विकास का आधार स्तंभ बताया। छत्तीसगढ़ भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल ने कहा कि श्रमिकों के हितों के लिए आर्थिक विकास हो सके इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के जीवन पर्यन्त तक की महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सफी अहमद ने कहा की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार की आर्थिक नीति बेरोजगारी दूर करने और लोगों को रोजगार

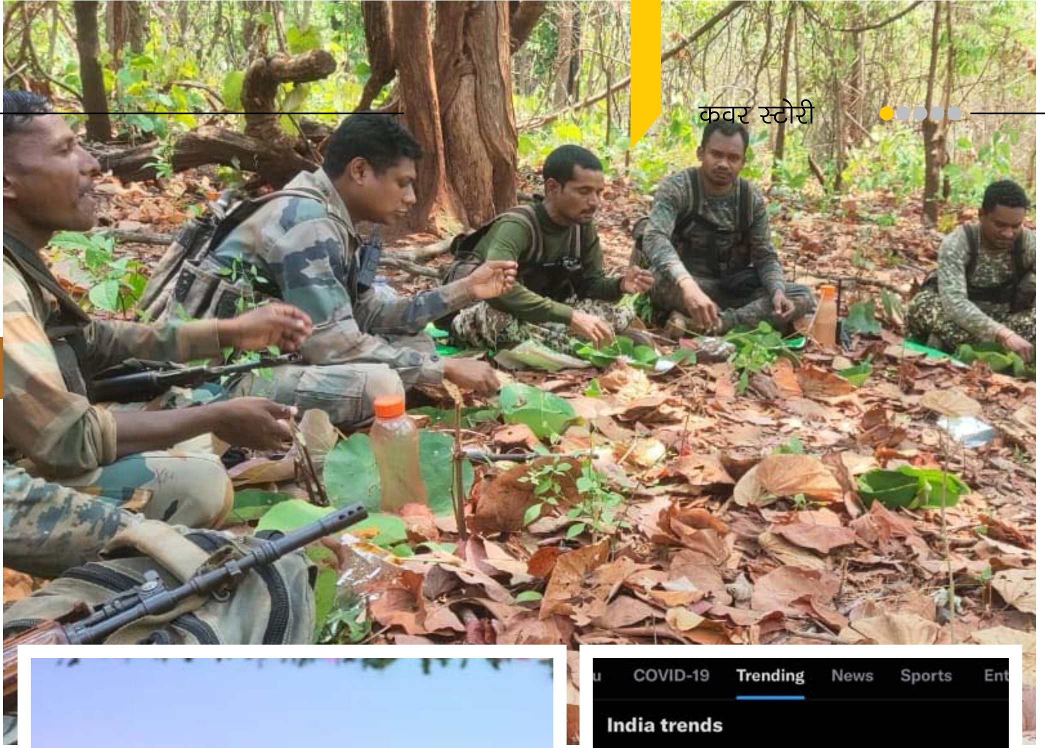

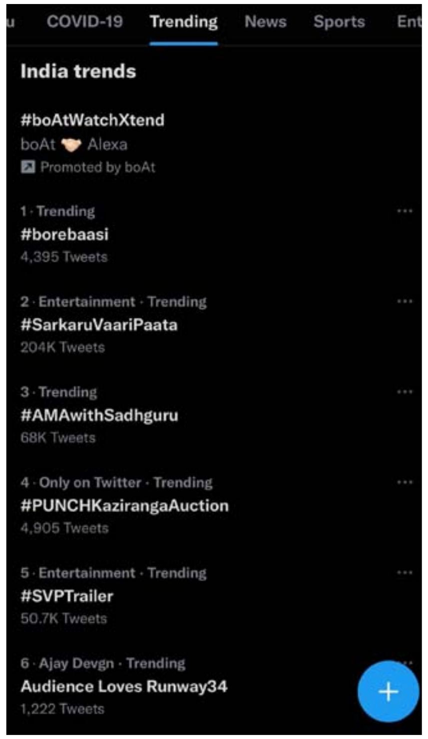

कवर स्टोरी

दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे राज्य में गरीबों, मजदूरों और किसानों का विश्वास सरकार के प्रति बढा है।

सीएम सर आपने बचपन और घर की याद दिला दी

नारायणपुर में तैनात जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और डीआरजी के जवानों ने बोरे बासी खाया। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ शासन के आह्वान पर मजदूर दिवस के अवसर पर जवानों ने भी बोरे बासी खाया। बोरे बासी खाकर जवान आत्मविभोर हो गए और बोले धन्यवाद सीएम सर, आपने बचपन और घर की याद दिला दी। जवानों ने कहा कि अब हम प्रयास करेंगे कि गर्मियों में अक्सर बोरे बासी खाएँ। डीआरजी टीम प्रभारी मुकेश्वर ध्रुव ने कहा कि गर्मी के दिनों में अगर किसी दिन रात चाँवल बच जाएगी तो वे जवानों के साथ सुबह बोरे बासी जरूर खाएँगे। जिला पुलिस बल, नारायणपुर के कुछ जवानों में अपने सोशल मीडिया अकॉउंट में बोरे बासी का फोटो भी शेयर किया है।

छत्तीसगढ़ का ह्यबोरे-बासीह्न छाया सोशल मीडिया पर

सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ का #ङ्गश्रें्र नंबर-1 पर ट्रेंड कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ियों से मजदूर दिवस पर बोरे-बासी खाकर अपनी छत्तीसगढ़िया संस्कृति और श्रमिकों को सम्मान देने की अपील पर देश-विदेश में बसे छत्तीसगढ़वासियों द्वारा बोरे-बासी खाकर अपनी फोटो-वीडियो रोचक कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर हैश टैग #ङ्गश्रें्र के साथ शेयर की जा रही है।

बोरे-बासी छत्तीसगढ़ का पारंपरिक भोजन है, पोषक तत्वों से भरपूर इस व्यंजन का छत्तीसगढ़ में किसान, मजदूर, अमीर-गरीब सहित सभी लोग, हमेशा से सभी बड़े चाव से खाते हैं। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपील पर कोने-कोने में बसे छत्तीसगढ़वासियों ने बोरे-बासी खाकर अपनी गौरवशाली परंपरा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया है। बोरे-बासी छत्तीसगढ़ का ऐसा भोजन है जो बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रात भर रख कर बनाया जाता है। फिर सुबह उसमें हल्का नमक डालकर, भाजी, टमाटर की चटनी, अचार और कच्चे प्याज के साथ खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः सुबह बासी का ही नाश्ता करते हैं। बोरे बासी खाने से न सिर्फ गर्मी और लू से राहत मिलती है, बल्कि बीपी कंट्रोल रहता है डि-हाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है।

गढ़कलेवा में बोरे बासी

मुख्यमंत्री के आव्हान पर ही संस्कृति विभाग द्वारा गढ़कलेवा में बोरे बासी थाली का शुभारंभ किया गया है। लोग चाव के साथ मुख्यमंत्री के आव्हान पर बोरे बासी खाकर श्रम को सम्मान देने के इस अभियान में भागीदारी बने। राज्य प्रशासनिक अधिकारी भी बोरे बासी खाकर तृप्त हुए और ठंडकता महसूस की।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डिप्टी कलेक्टर लिंगराज सिदार ने बासी खाकर प्रतिक्रिया में बताया वे बचपन में अक्सर बासी खाते थे। भले ही अब बासी खाने का अवसर कम मिलता हो, लेकिन जैसे ही बासी खाने का मौका मिलता है, तो वह बासी जरूर खाता है। सिदार अपने साथियों के साथ गढ़कलेवा में विशेष रूप से बोरे बासी खाने आए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी हेमंत सिदार, निखिलेश सिदार सहित अन्य लोगों ने भी उत्साह के साथ बोरे बासी का लुप्त उठाया।

बोरे-बासी होटलों के मेन्यू में हुआ शामिल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर लोगों से बोरे-बासी खाकर श्रमिकों का सम्मान करने की अपील की थी। जिसका छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन की ओर से स्वागत करते हुए अपने होटलों में बोरे-बासी की व्यवस्था की गई। साथ ही कई होटलों में बोरे बासी को अपने मेन्यू में शामिल कर लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस पहल की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बोरे-बासी के सेवन को प्रोत्साहित करने पर आभार जताते हुए कहा कि स्थानीय खान-पान को छत्तीसगढ़िया सम्मान के साथ जोड़कर आपने हमारी संस्कृति, विरासत और परंपरा को संजोने का अद्भुत कार्य किया है। इसके साथ ही होटल सायाजी और ग्रैंड इम्पेरिया ने अपने विदेशी मेहमानों को छत्तीसगढ़ी बोरे-बासी का स्वाद चखाया।

छत्तीसगढ़ में खुलेगा ग्रामीण उद्योग पार्क

गांवों में रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने और किसानों, युवाओं, महिलाओं को उन्हीं के गांवों में नवाचार और उद्यम से जोड़ने की फ्लैगशिप योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत ग्रामीण उद्योग केंद्रों की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करने कार्यशाला का आयोजन राज्य योजना आयोग द्वारा योजना भवन नवा रायपुर में किया गया। ग्रामीण उद्योग केंद्रों के कार्यक्षेत्र क्रियान्वयन के सबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न विभाग के उपस्थित अधिकारियों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के क्रियान्वयन एवं संचालन पर अपने सुझाव दिए, इसके आधार पर योजना के आगामी क्रियान्वयन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने पर भी गहन विमर्श हुआ।

राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में के केन्द्र में किसान न्याय योजना और नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना का महत्वपूर्ण उल्लेख है। जिसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनियोजित ढंग से हो रहा है। इसकी चचाएँ राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। हमारी योजना को अन्य राज्यों ने अपने यहां लागू करने, विचार करने के उद्देश्य से टीमें छत्तीसगढ़ आ रही हैं। गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज की संकल्पना की थी, छत्तीसगढ़ सरकार उसे साकार कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम गौठानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर संग्रहण, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था की जा सके। युवा किसानों को उद्यम नवाचार से जोड़ने, गांव के पढ़े-लिखे युवा जो गांव में ही रहकर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन्हें दिशा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है।

रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का विकास

मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने बताया कि हम गौठानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, प्रथम चरण में गौठानों में गाय के संधारण, गाय से संबंधित इंडस्ट्रीज के लिए कार्य हुआ। अब हम दूसरे चरण में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का विकास करेंगे। 85 हजार महिलाओं ने मिलकर 56 लाख क्विंटल गोबर खाद का उत्पादन किया है, वर्तमान में देश में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा 20 लाख क्विंटल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे पास तैयार सुरिक्षत है। महिला समूहों को अब तक 36 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने प्रदेश के किसानों को समृद्ध किया है, अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यंग जनरेशन को उद्यम हेतु प्रेरणा देने एवं समावेशी आर्थिक उत्थान केन्द्रित योजना है। हम इन जगहों पर जमीन, बिजली, पानी, शेड, बैंकिंग लिंकेज, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, स्टोरेज, व्यावसायिक सुविधा विकसित करेंगे। इस योजना में राज्य स्तर पर नवा सेवाग्राम सोसाइटी, जिला स्तर पर गांधीग्राम, ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र, पंचायत स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का चैनल बनाकर कार्य करेंगे।

शिक्षुओं को शत-प्रतिशत रोजगार मिले

राज्य के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि अधिकारियों ने अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी, जिसमें ट्राइबल क्षेत्रों में विशेष रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के महत्व, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, रोजगार की सुनिश्चितता, मार्केट डिमांड के अनुरूप उत्पादन, गुणवत्ता मानकों, विकास एवं इनफ्रास्ट्रक्चर, खरीदी एवं भण्डारयण नियमों में शिथिलीकरण, परिवहन एवं क्षेत्रीय महत्व के आधार पर अनेक बिंदुओं पर प्रश्न एवं सुझाव दिए।रूरल इंडस्ट्रियल पार्क फ्लैगशिप योजना के प्रमुख संचालक डॉ. आलोक शुक्ला ने कहा कि हमें जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और प्रभावोत्पादक को देखते हुए कार्य करना है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना अपने लक्ष्य को व्यवहारिक रूप से निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर सके इसके लिए हम सब को विशेष ध्यान देना होगा। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन क्षेत्रों में वे प्रशिक्षण करवा रहे हैं, उन प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को शत-प्रतिशत रोजगार मिले। इसके लिए जरूरी है कि हमारा उत्पाद गुणवत्ता के पैमाने पर खरा एवं प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता का हो, ताकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी हो सके। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का उद्देश्य गांवों को मजबूत अर्थव्यवस्था संचालित करने के लिए तैयार करना है। ग्रामीण युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिले, वे नवाचार की ओर प्रेरित हों, उद्यम स्थापना के लिए प्रोत्साहित हों। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें रोजगारोन्मुखी नीतियों पर काम करना होगा जो परिणाममूलक हों। डॉ. शुक्ला ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों से अपना शत-प्रतिशत देते हुए कार्य करने की बात कही।

कृषि से उद्योग की राहें

छत्तीसगढ़ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उद्योगों से जोड़ने की पहल नई उद्योग नीति में की गई है। राज्य में कृषि उत्पादनों और वनोपजों के वैल्यूएडिशन के जरिए भी लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में पिछड़े वर्गों को उद्योगों से जोड़ने के नये प्रावधान भी किए गए हैं। राज्य में उद्योग हितैषी नीतियों के कारण नये-नये उद्योगों की स्थापना हो रही है। युवाओं को उद्यमियता से जोड़ने के लिए नये स्टार्टअप विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में कृषि से उद्योगों को जोड़ने की पहल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोर सेक्टर के साथ ही नये क्षेत्रों में भी उद्यमियों को आकर्षित किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों में कुल एक हजार 751 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है, जिसमें 19550.72 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इससे 32 हजार 912 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस दौरान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित 478 इकाईयां स्थापित हुई है, जिसमें कुल 1167.28 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा 6319 व्यक्तियों को रोजगार भी मिला है।

फूड पार्को की स्थापना-

किसानों की फसल का वैल्यूएडिशन कर नये उत्पाद तैयार करने के लिए 200 फूड पार्कों की स्थापना के लिए काम शुरू कर दिया गया है। लगभग 110 फूड पार्कों के लिए जमीन का चिन्हांकन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में फुडपार्क स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, आने वाले वर्षों में राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित कई उद्योग भी स्थापित होंगे और जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण मिशन -

छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत उद्योगों का उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण तथा उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी दोनों क्षेत्रों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास, प्रसंस्करण केंद्र व संग्रहण केंद्र भी योजना में सम्मिलित है।

एथेनॉल प्लांट

सहकारिता के क्षेत्र में देश में पहली बार पीपीपी मोड पर कंवर्धा जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए अनुबंध किया गया है। इसी प्रकार कोण्डागांव जिले के कोकड़ी गांव में प्रस्तावित मक्का प्रसंस्करण ईकाई में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

पिछड़ा वर्ग को प्रोत्साहन-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के उद्यमियों के लिए स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु अंशपूंजी सहायता के रूप में अनुदान योजना लागू की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के बंद एवं बीमार उद्योगों को क्रय किए जाने पर नवीन पंजीयन के साथ ही अनुदान एवं छूट की भी पात्रता देने का निर्णय लिया गया है।

3 साल में 167 एमओयू -

नए उद्योग की स्थापना के लिए जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक कुल 167 एमओयू किए गए हैं। जिनमें 78 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। जिसके तहत 90 इकाइयों ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 2,750 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। कुछ इकाइयों ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिए हैं।

508 स्टार्टअप इकाईयां पंजीकृत -

औद्योगिक नीति 2019-24 में स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज लागू की गई है। जिसके तहत विगत 3 वर्षों में 508 स्टार्टअप इकाईयां पंजीकृत हुई है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इकाइयों को छत्तीसगढ़ में स्थापित होने पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की गई है। इसके तहत ब्याज अनुदान, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क पर छूट, स्टांप शुल्क में छूट, परियोजना प्रतिवेदन में छूट इत्यादि छूट प्रदान की जा रही है।

नवीन उद्योगों के लिए रियायत-

औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 16 प्रमुख से एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, सेवा केंद्र बीपीओ 3 डी प्रिंटिंग, बीज ग्रेडिंग इत्यादि सेवाओं को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महिला स्व-सहायता समूह एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को उद्योग निवेश प्रोत्साहन हेतु पृथक से वगीर्कृत किया गया है। इसके अलावा मेडिकल एवं लेबोरेटरी उपकरण, मेडिकल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर, आक्सीजन कन्सनट्रेटर, फेस मास्क, कोविड जैसे संक्रमण वाली बीमारियों के टेस्ट में उपयोग होने वाले उपकरण, टीका बनाने के उपकरण को प्राथमिकताओं वाली उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विकास पथ पर तेजी से बढ़ता कदम

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़ का 28 वां नवगठित जिला है। 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आए जिले की दूसरी वर्षगांठ 10 फरवरी 2022 को अरपा महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों, वनवासियों, मजदूरों और गरीब तबकों के कल्याण और इनके आर्थिक तरक्की के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी सोंच के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले की जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी कार्यालयों से संबंधित काम काज को सुलभ-सरल बनाने के लिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले का गठन किया है। नये जिले को लघु रूप मे जीपीएम कहते है।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और देश की राजधानी नई दिल्ली से सीधे रेलमार्ग से जुड़ा है। जिले की कुल क्षेत्रफल 2307.39 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 3 लाख 36 हजार 420 है। जिले में तीन तहसील-गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही, दो अनुविभाग पेण्ड्रारोड एवं मरवाही, तीन जनपद पंचायत गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही, दो नगर पंचायत पेण्ड्रा एवं गौरेला और 162 ग्राम पंचायते तथा 225 गांव शामिल है।

नए जिले को जल्द से जल्द व्यवस्थित रूप से स्थापित करने और प्रशासनिक काम-काज में गति लाने के लिए कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रियाएं प्रगति पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में जिले के प्रभारी एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, विधायक डॉ. के. के. ध्रुव और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से कम संसाधनों के बावजूद भी पिछले दो वर्षो में जिले में अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है।

जन आकांक्षाओं के अनुरूप यहां के स्थानीय निवासियों को सरकारी सेवाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है इसके तहत भर्ती प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार द्वारा लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इस पर भी जिले में तेजी से काम शुरू हो गया है। नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत जिले में 97 प्रस्तावित नये इकाईयों ने उद्यम आकांक्षा प्राप्त किया है। जिसमें 55 करोड़ 94 लाख रुपए का पूंजी निवेश और 979 लोगों का रोजगार प्रस्तावित है।

जिले में अधोसंरचना विकास के तहत 42 करोड़ रुपए की लागत से गौरेला रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया गया। 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से कंचनडीह-बारीउमराव मार्ग पर सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया। पुल बनने से 10 गांवों के लगभग 12 हजार 135 रहवासियों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिल रही है। इसी तरह 5 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से सेमरदर्री-पसान मार्ग में सुखाड़ नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया है। इससे 6-7 ग्रामों के लगभग 8 हजार 576 रहवासियों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिल रही है।

जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। मटियाडांड जलाशय जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शीर्ष कार्य के लिए 37 लाख 12 हजार स्वीकृत की गई है। शीर्ष कार्य के निविदा कार्य की लागत 25 लाख 60 हजार रुपए है। यह कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण होगा। इससे 50 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में सिंचाई होगी। राजाडीह जलाशय के लिए लगभग 6 करोड़ 35 लाख स्वीकृति किया गया है, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके निर्माण से 250 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में और 130 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी मौसम में सिंचाई में वृद्धि होगी। सोन नदी पर कोलबिर्रा जलाशय मध्यम परियोजना निर्माण के लिए प्रथम चरण में 208 करोड़ 10 लाख स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस योजना से 3500 हेक्टेयर में खरीफ और 1000 हेक्टेयर में रबी मौसम में सिंचाई प्रस्तावित है।

जिले वासियों को निर्वाध बिजली और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए पिछले दो वर्षो बेहतर कार्य हुए है। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत बस्ती, दुबटिया और आमाडांड में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंन्द्रो की स्थापना की गई है। जिले में बिजली बिल हॉफयोजना के तहत धरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट प्रतिमाह खपत की सीमा तक के 20 हजार 242 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। पेयजल

के लिए विभिन्न योजनाओं-नलकूप, हैण्डपंप, नलजल, सोलर पंप अधारित जल प्रदाय, जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन, मिनी माता अमृत धारा नलजल और जल आर्वधन योजना के माध्यम से समुचित प्रबंध किए गए है।

जिले के किसानों और खेती किसानी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों मे गति आई है। भुईया कार्यक्रम के अंतर्गत जिले मे समस्त भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है। जिले में 1610 अविवादित नामांतरण, 1551 विवादित नामांतरण, 57 अविवादित खाता विभाजन, 792 विवादित खाता विभाजन और 786 सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। व्यपवर्तित भू-भाटक योजना के तहत जिले में 64 हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। इससे शासन को 9 लाख 20 हजार 983 रुपए की आय प्राप्त हुई है। जिले में 1676 (रकबा 541 हेक्टेयर) व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 106 (रकबा 16450 हेक्टेयर) सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 59 (रकबा 43717.) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है।

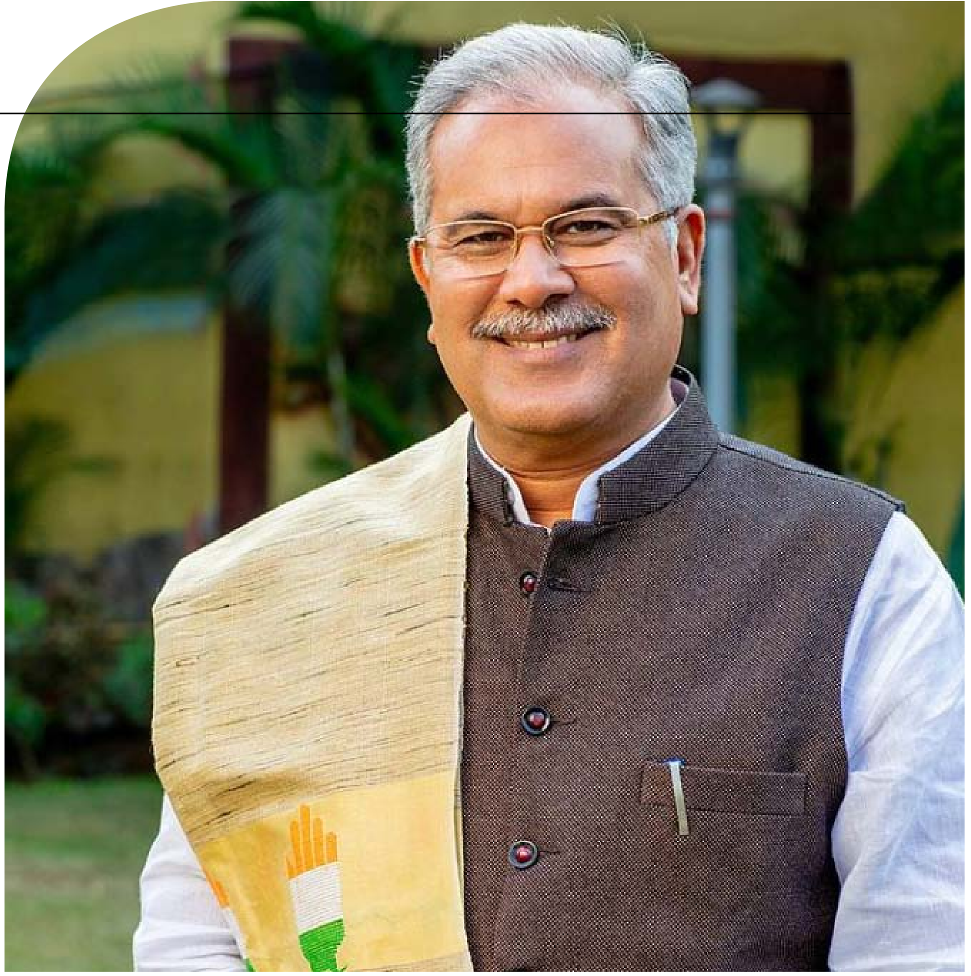

जिले में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3029 व्यक्तियों को चिन्हाकित किया गया है। जिले में लगभग 68 हजार 126 किसान हैं। इनमें लगभग 51 प्रतिशत सीमांत, 39 प्रतिशत लघु किसान एवं 10 प्रतिशत दीर्घ किसान हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 13 हजार 423 किसानों को 75 करोड 72 लाख रुपए भुगतान की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 20 हजार 887 किसानों के फसलों का बीमा किया गया है। इसमें से 2983 किसानों को 3 करोड़ 11 लाख 57 हजार रुपए दावा राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 हजार 306 किसानों को नौवी किश्त के रूप में 1 करोड़ 66 लाख 12 हजार रुपए का भुगतान किया गया है।

स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने वन धन योजना के तहत 52 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए मनरेगा योजना से 19 लाख रुपए की लागत से खोडरी एवं दानीकुण्डी में वन धन केन्द्र स्थापित किया गया है।

जिले में शैक्षणिक विकास के तहत विकासखण्ड गौरेला के सेमरा, विकासखण्ड पेंड्रा के भरापारा और मरवाही में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन हो रहा है। इन विद्यालयों में 1348 विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इन विद्याालयों में लाईब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, शारीरिक शिक्षा के साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की सुविधायें प्राप्त है। जिले मे सीख कार्यक्रम कोरोना काल में ग्रामीण बच्चों के लिए वरदान साबित हुई, जब कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहे, बच्चों की शिक्षा का कोई स्त्रोत नहीं था, तब सीख मित्रों ने बच्चों को शिक्षा दी। यह कार्यक्रम बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों के लिए भी फायदेमंद साबित हुई। सीख कार्यक्रम के तहत चलाय गए पुस्तक दान अभियान से जिले के 222 गांवों में सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण किया गया। किताब दान अभियान में जिले के दान दाताओं के साथ ही प्रदेश एवं अन्य राज्यों से भी सहयोग प्राप्त हुआ। अभियान में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, उद्योगपति, व्यवसायी, अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि सहित अनेक नागरिकों की सहभागिता से 13 लाख 32 हजार रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। सामुदायिक पुस्तकालयों में 26 हजार 640 रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही है।

जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र मे काफी विकास हुआ है। जिले में 94 स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे है। इनमें से 52 स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में 87 हजार 204 व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाए गए है। इनमे 2537 लोगों को आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य सहायता राशि दी गई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत 42 हाट बाजारों में 26 हजार 877 लोगों का इलाज किया गया।

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 लाख 8 हजार 147 राशनकार्डधारी लाभान्वित हो रहे है। इनमें 28 हजार 167 अंत्योदय, 73 हजार 657 प्राथमिकता वाले, 95 निःशक्तजन, 319 निराश्रित और 5 हजार 909 सामान्य एपीएल राशनकार्डधारी शामिल है। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 28 हजार 114 हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। मुख्यमंत्री कन्या के विवाह योजना के तहत 73 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया।

जिले में जैविक खेती, वनोंषधि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला निरन्तर विकास पथ पर बढ़ रहा है और आने वाले समय में विकासशील जिला बनकर प्रदेश और देश को आकर्षित करेगा।

देश में बेरोजगारी दर बढ़ी

देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% हो गई, जो मार्च में 7.60% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि शहरों में बेरोजगारी दर 9.22% हो गई है, जो मार्च में 8.28% थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर घटी है। गांवों में दर 7.18% रही, जो मार्च में 7.29% थी। हरियाणा में बेरोजगारी दर 34.5% और राजस्थान में 28.8% दर्ज की गई है। यह देश की बेरोजगारी दर से चार गुना अधिक है। इससे पहले मार्च में प्रदेश में बेरोजगारी दर 25.5% थी। यानी एक माह में ही बेरोजगारी दर 3.3% बढ़ी है। वहीं फरवरी में रिकॉर्ड 32.3% थी। लेकिन एक महीने में यह दर फिर बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे सरकारी नौकरियों की कमी तो है ही। कोरोना से जो उद्योग उबर रहे थे, उन पर रूस-यूक्रेन युद्ध और अब बिजली संकट का साया पड़ा है। इससे उत्पादन व रोजगार प्रभावित हुए।

मार्केट से 38 लाख कामगार घटे, करोड़ों ने तलाश छोड़ी

सीएमआईई के अनुसार, देश में आर्थिक गतिविधियां कमजोर होने के कारण अप्रैल में 38 लाख कामगार कम हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर रोजगार के लिए योग्य करोड़ों लोगों ने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार में काम उपलब्ध नहीं है। डेलॉय इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार का कहना है कि कोरोना के दौर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जॉब क्रिएशन को लेकर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। यह स्थिति लगभग सभी सेक्टर्स में बनी हुई है।

कोरोनाकाल में रोजगार छिने वे अब तक पटरी पर नहीं

आखिर में लेवल-2 की परीक्षा तो रद्द की करनी पड़ी। लेवल-1 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब चल रही है। वहीं लेवल-2 के पुराने पदों को मिलाकर रीट-2022 का आयोजन होगा। आरएएस-2021 में भी यही स्थिति हुई। प्री पर विवाद हुआ तो मेन्स से दो दिन पहले इसे भी स्थगित कर आगे खिसकाना पड़ा। कांस्टेबल भर्ती में 18 लाख, वीडीओ भर्ती में 14 लाख तो वनपाल-वनरक्षक भर्ती तक में 22 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। कोरोनाकाल में रोजगार छिने तो वे अब तक पटरी पर नहीं आ पाए हैं।

-नंदसिंह नरूका, पूर्व अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड

पेपर लीक और नियुक्तियों में देरी से बढ़ी बेरोजगारी

बेरोजगारी की स्थिति चौंकाने वाली है। सरकार हर साल बजट में भर्तियों की घोषणा तो कर देती है, लेकिन उनके क्रियान्वयन को लेकर कोई योजना नहीं रहती। भर्ती कराने वाली एजेंसियों के पास भर्ती कैलेंडर तक नहीं होता। इसके अलावा पेपर लीक, नकल और फर्जी अभ्यर्थियों के चयन के कारण भर्तियों की विश्वसनीयता भी खत्म होती जा रही है। हाल में 5 बार स्थगित करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट-2021 का आयोजन हुआ तो इसमें भी पेपर लीक हो गया। रिजल्ट में भी गड़बड़ी के बात सामने आई हुई।

अब आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री

90 विधानसभा में जाएंगे सीएम

लोगों की जानेंगे समस्याएं

सीएम भूपेश बघेल का तूफानी दौरा शुरू हो चुका है। इस महीने सीएम ने सरगुजा से दौरे की शुरुआत की है। सबसे खास बात यह है कि सीएम आम लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही 90 विधानसभा का दौरा करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले वे कुसमी में आम जनता से रूबरू चर्चा के लिए आयोजित ह्यभेंट-मुलाकातह्य में कुसमी के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

नगर पंचायत कुसमी के वार्ड क्रमांक-2 में आम के पेड़ की ठंडी छांव में मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए पैदल चलकर स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री आम जनता की मांग पर कुसमी-सामरी-बलरामपुर पहुंच मार्ग में कंठी घाट के पास करीब 8 किलोमीटर सड़क डामरीकरण, कुसमी में आलू, टाउ और मिर्ची के फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना, कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नई तकनीक वाली एक्सरे मशीन, आईटीआई में नए ट्रेड खोलने आईटीआई के नए भवन निर्माण तथा नगर पंचायत कुसमी में फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था करने की घोषणा की। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुसमी से कोरंधा होकर लातेहार सड़क को राजकीय राजमार्ग बनाने के लिए झारखण्ड सरकार से चर्चा करने का आश्वासन दिया। कुसमी में बिजली कटौती और ओव्हर लोड की समस्या की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के दौरान सभा में मौजूद प्रिया यादव नाम की बच्ची के दिल के ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसकी मां को पास बुलाकर बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। मां ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्ची का स्वास्थ्य अब बहुत बेहतर है। श्री बघेल ने बच्ची को गोद में उठाकर दुलारा और आशीर्वाद दिया। इस बच्ची प्रिया यादव का शासन से मिली 3.5 लाख रुपए की राशि से इलाज हुआ है, बच्ची की मां ने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। श्री बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं से उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली। समूह की महिलाओं ने उनके समूह द्वारा तैयार की गई सामग्री की टोकरी मुख्यमंत्री को भेंट की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने तिलक लगाकर नर्सिंग स्टॉफ का किया स्वागत

मुख्यमंत्री ने बरियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोषण पुनर्वास केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां इलाज कराने आये मरीजों से बात कर हाल पूछा। श्री बघेल ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओ की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से लेकर नर्सों और अन्य स्टाफ से भी बात की और लोगो को बेहतर इलाज की सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में दवाई और अन्य उपकरण आदि भी अस्पताल में उपलब्ध रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को देखते हुए लू से बीमार मरीजों का तत्काल इलाज करने सभी इंतजाम और दवाई, ग्लूकोस आदि की व्यवस्था भी पहले से ही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरियों द्वारा लोगों को दी जारी बेहतर सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य केन्द्र स्टॉफ का तिलक लगाकर स्वागत किया।

बच्चों में भी उत्सुकता नजर आ रही

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात अभियान को लेकर बच्चों में भी उत्सुकता नजर आ रही है। सामरी विधानसभा के बरियो में जब बच्चों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने की जानकारी मिली तो उनके साथ फोटो खिंचाने की चाहत में वे सुबह से ही आंगनबाड़ी केन्द्र में इकट्ठे होकर इंतजार करते रहे। यहाँ साक्षी बेग नाम की बच्ची सुबह से ही मुख्यमंत्री संग फोटो खिंचाने के लिए बैठी हुई थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल बरियो के आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण करने पहुँचे, तो उन्हें इस बात की खबर मिली। मुख्यमंत्री बघेल बच्चों के पास गए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। स्नेही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बच्चों को दुलार करते हुए बातचीत भी की। बघेल ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओ की जानकारी ली।उन्होंने डॉक्टरों से लेकर नर्सों और अन्य स्टाफ से भी बात की और लोगो को बेहतर इलाज की सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में दवाई और अन्य उपकरण आदि भी अस्पताल में उपलब्ध रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को देखते हुए लू से बीमार मरीजों का तत्काल इलाज करने सभी इंतजाम और दवाई, ग्लूकोस आदि की व्यवस्था भी पहले से ही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को ब्रांडेड दवाईयां नही लिखने और केवल जेनेरिक दवाई ही लिखने के निर्देश दिए। यहाँ उन्होंने वार्ड में भर्ती बाघा निवासी नव प्रसूता अनिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई दी।मुख्यमंत्री ने नव निहाल को गोद में ले दुलार किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने अनिता की बेहतर देखभाल और इलाज के निर्देश उपस्थित डॉक्टर को दिए। श्री बघेल में नव प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित राशि का चेक,बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और डॉ खूब चंद बघेल स्वास्थ्य योजना का बीमा कार्ड भी प्रदान किया।

नव प्रसूता को दी बधाई

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को ब्रांडेड दवाईयां नही लिखने और केवल जेनेरिक दवाई ही लिखने के निर्देश दिए। यहाँ उन्होंने वार्ड में भर्ती बाघा निवासी नव प्रसूता श्रीमती अनिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने नव निहाल को गोद मे ले दुलार किया और आशीर्वाद दिया। श्री बघेल में नव प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित राशि का चेक,बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का बीमा कार्ड भी प्रदान किया।

बच्चों ने सुनाया राजगीत

स्वामी आत्मा नंद इंग्लिश मीडियम स्कूल राजपुर के विद्यार्थियों ने राज गीत गाया। इस दौरान गायत्री महिला स्व सहायता समूह, माहेश्वरी महिला स्व सहायता समूह, लक्ष्मी स्व सहायता समूह, रोशनी स्व सहायता समूह की सदस्यों ने बताया कि वे सरसों तेल, एलईडी बल्ब, कपूर से लेकर वर्मी खाद तक बना रही हैं। गोबर खरीदी से उन जैसी कई महिलाओं को रोजगार मिला है। समूह की सदस्यों ने गांव में ही आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री की सोच को विकास का आधार बताया और सरकार की योजना की तारीफ की।

लोगों ने सरकार के कार्यक्रमों को सराहा

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में किसान उदयराम, मनीजर, मोहन,और लाला ने खेती किसानी को बढ़ाने और किसानों को फायदा पहुचाने वाली योजनायें लागू करने के लिए भी मुख्यमंत्री श्री बघेल को धन्यवाद दिया। युवाओं को आगे बढ़ाने, नेतृत्व क्षमता को निखारने और युवाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी युवा मितान क्लब बनाने के लिए भी बरियों तथा अमडीपारा के युवाओं ने मुख्यमंत्री की सराहना की। भूमिहीन किसानो के लिए हर साल आर्थिक सहायता देने की भूमिहीन किसान कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए भी रेगहा और अधिया में खेती कर रहे भूमिहीन किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात अभियान के पहले दिन सामरी विधानसभा क्षेत्र के कुसमी और शंकरगढ़ के बाद तीसरे व अंतिम पड़ाव बरियों रहा। जहां उन्होंने मंडी परिसर में आमजनता से रू-ब-रू हुए और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान ग्रामीणों के मांग पर अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री बघेल ने यहां जन समुदाय से चर्चा करते हुए बरियों में एक विद्युत सब-स्टेशन, पंजीयन कार्यालय और मंगल भवन सहित औद्योगिक पार्क के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर त्वरित पहल करते हुए हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने इस दौरान बरियों तक सुगम आवागमन सुविधा के लिए 5 किलोमीटर सड़क मार्ग के निर्माण की घोषणा करते हुए पूर्व से स्वीकृत सूरजपुर-कल्याणपुर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री बघेल ने शिवमंदिर तालाब का सौदर्यीकरण, पार्क और मिनी स्टेडियम निर्माण, आरा में धान खरीदी केन्द्र और भिलाईखुर्द में गौठान प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने इस दौरान गांवों में एक-एक देवगुड़ी के निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक को प्रस्ताव देने के लिए कहा। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि गांव में एक देवगुड़ी के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। मुख्यमंत्री ने बरियों में नए तहसील कार्यालय भवन के निर्माण और पहाड़ी कोरबा गांव तक 20 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी प्रदान की।

सेल्फी लेने की लगी होड़

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनके साथ लोगों की सेल्फी लेने की होड़ लगी थी। किसान, मजूदर, युवा और बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ उत्साह के साथ सेल्फी ली। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों और युवाओं का उत्साहवर्धन किया।

न्याय योजना में जुड़ा अनिता गुप्ता का नाम

मुख्यमंत्री श्री बघेल बरियों स्वास्थ्य केन्द्र इलाज करा रहे दिनेश गुप्ता से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। दिनेश गुप्ता की पत्नी अनिता गुप्ता ने बताया कि वे पास ही के गांव बघिमा में रहती हैं। उनके पास जमीन, खेत नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को तत्काल उनका पंजीयन भूमिहीन कृषि मजूदर न्याय योजना में करने और 7000 रुपए सालाना की सहायता देने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बघेल ने मालती तिवारी के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण का परीक्षण कर उन्हें नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मालती तिवारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पति शिक्षाकर्मी थे और उनका संविलयन आदेश हो गया था। उनकी मृत्यु पश्चात अब उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिली है।

दांतों में दर्द होने के पीछे दांतों की सफाई सही से ना होना, कैविटी, बैक्टीरियल इंफेक्शन, कैल्शियम की कमी आदि जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में प्याज दांतो के दर्द को दूर करने में उपयोगी है, जानते हैं इस्तेमाल करने का तरीका...

दांतों में रहता है दर्द? इस सब्जी को नमक और नींबू के साथ रगड़ें

जब किसी व्यक्ति के हाथों में दर्द होता है तो उसका प्रभाव उसके खाने-पीने पर भी पड़ता है और व्यक्ति सही से चबा भी नहीं पाता है। दांतों में दर्द कैविटी के कारण भी हो सकता है या इसके पीछे बैक्टीरियल इंफेक्शन, कैल्शियम की कमी या दातों की ठीक से सफाई ना करना आदि भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में बता दें कि प्याज के इस्तेमाल से दांतों के दर्द को दूर किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि प्याज का इस्तेमाल कैसे किया जाए।

कैसे करें दांतों पर प्याज का इस्तेमाल

- प्याज और नींबू का एक साथ इस्तेमाल करने से दांतों की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप आप एक कटोरी में नमक और नींबू के रस का मिश्रण तैयार करें। अब आप बने मिश्रण को प्याज के टुकड़ों के माध्यम से रगड़ें। ऐसी करने से न केवल कैविटी से राहत मिल सकती है बल्कि दांतों के दर्द से राहत मिल सकती हैं।
- अकसर लोगों को लगता है कि अगर वे दांतों पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो बदबू आने जैसी समस्या हो सकती है।

लेकिन बता दें कि अगर प्याज का इस्तेमाल नमक के साथ करें तो इससे न केवल दांतों की सफाई अच्छे से हो सकती है बल्कि दांतों के दर्द को भी दूर किया जा सकता है। ऐसे में आपको प्याज को दो टुकड़ों में काटना होगा और उसके ऊपर नमक छिड़ककर दांतो पर रगड़ना होगा, ऐसा करने से लाभ मिल सकता है।

नोट झ ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि दांतों के लिए प्याज बेहद उपयोगी है। लेकिन यदि आपको कोई और समस्या है तो या दर्द की समस्या बढ़ती ही जा रही है ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर ही प्याज का इस्तेमाल करें।

यूक्रेन को हथियारों देगा जर्मनी

रूस की धमकियों के बावजूद जर्मनी यूक्रेन को 50 गेपर्ड टैंक सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि ऐसा करने के बाद दुनिया के मंच पर उसे कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा।

वायुसेना ने 87 सैनिक अड्डों को अपना निशाना बनाया

एक ही रात में यूक्रेन के 500 सैनिक मारे गए

जर्मनी ने यूरोपियन सुरक्षा को लेकर जो भी वादे किए थे, यूक्रेन को टैंक बेचकर उसने उन सभी वादों को ताक पर रख दिया है।

जर्मनी की डिफेंस इडस्ट्री फरवरी से ये टैंक यूक्रेन को बेचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन स्कोल्ज की सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। जिसकी वजह से जर्मनी के लोग सरकार की खूब आलोचना कर रहे थे। रूस एक तरफ यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसके खुद के शहर में हालात बिगड़े हुए हैं। पश्चिमी रूस में उल्यानोवस्क शहर के एक किंडरगार्डन स्कूल पर गोलबारी का मामला सामने आया है। इस हमले में कुल चार लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में दो बच्चों की भी मौत हुई है। रूस-यूक्रेन युद्ध को करीब दो महीने हो गए हैं। इस बीच रूस की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा दावा किया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि रूसी वायुसेना ने 87 सैनिक अड्डों को अपना निशाना बनाया था। इसमें खार्किव के भी दो सैनिक अड्डे शामिल थे। इस कार्रवाई में एक ही रात में यूक्रेन के 500 सैनिक मारे गए। इसके अलावा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबासाइट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। जिसमें यूक्रेन के हथियार रखने वाली जगहों को कब्जे में लेने की बात कही गई है। इस वीडियो क्लिप में मिलिट्री टैंक और गाड़ियों को आते-जाते भी देखा जा सकता है। रूस ने आगे कहा कि उसने यूक्रेन के गोला-बारूद, हथियार और दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है।

क्रू मेंबर्स को गोलीबारी की धमकी दी जा रही

रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के जनरल मिखाइल मिजितसेव ने दावा किया है कि यूक्रेन ने मारियुपोल समेत 7 बंदरगाहों पर 76 विदेशी जहाजों को आगे जाने से रोक दिया है। मिजितसेव ये भी कहा है कि 18 देशों के जहाजों को कीव अधिकारी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। इसके अलावा जहाजों के क्रू मेंबर्स को गोलीबारी की धमकी भी दी जा रही है।

रूस-यूक्रेन जंग से जुड़ी अहम खबरें

1986 में सोवियत संघ में स्थित चेर्नोबिल पावर प्लांट में भीषण परमाणु हादसा हुआ था। इससे प्लांट में मौजूद 40 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे के बाद प्लांट से निकले रेडिएशन से 50 लाख लोग प्रभावित हुए थे। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस जिस ब्रांस्क शहर से रसद हासिल कर रहा था, यूक्रेन ने वहां मिसाइल से हमले किए। इस हमले में ब्रांस्क के 2 ऑइल डिपो ट्रांसनेफ्ट-ड्रुज्बा में आग लग गई। ब्रांस्क एक लॉजिस्टिक हब है। दूसरी तरफ युद्ध को रोकने की डिप्लोमैटिक कोशिशें भी जारी है। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सीजफायर के लिए आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मॉस्को में मिलेंगे। इसके अलावा वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन भी जाएंगे।

यूरोप से परे भी पहुंचे जंग की आंच

यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर रायसीना डायलॉग में शामिल होने नई दिल्ली पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने चेतावनी दी है कि रूसी हमले का असर यूरोप की सीमा से परे भी होगा। इसके साथ ही उसुर्ला ने मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ते तालमेल पर पर बात की। रूस की आक्रामकता से इंडो-पैसिफिक रीजन भी प्रभावित हो सकता है।

जेलेंस्की का दावा- हमने 931 बस्तियों को आजाद कराया

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी सेना ने 931 बस्तियों को रूसी सेना का आजाद करा लिया है। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी सारी जमीन को रूसी सैनिकों से आजाद करा लेंगे। वहीं, खार्किव के गवर्नर का कहना है कि रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव ने यूक्रेन की मदद के लिए फंडरेजिंग प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने मीडिया से कहा- मैंने अपने सैलरी दान कर दी है और अपने देश के नागरिकों से भी ऐसा करने की अपील की है। यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने के लिए राजनीतिक के साथ सार्वजनिक एकता की भी जरूरत है।

परमाणु हथियार शामिल होंगे

- खेरसोन सिटी काउंसिल पर रूस का कब्जा, रूसी विदेश मंत्री बोले- अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियार शामिल होंगे।
- रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि परमाणु युद्ध का असल खतरा अभी भी है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो इसमें परमाणु हथियार शामिल होंगे और यह विनाशकारी होगा।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी सेना को लूटने के लिए अमीर घरों का पता दिया था।
- अमेरिका ने यूक्रेन को सोवियत काल के 165 मिलियन डॉलर मूल्य के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी।
- इंफो सेपियन्स एजेंसी के एक पोल के मुताबिक, 93% यूक्रेनी नागरिक यह मानते हैं कि उनकी सेना रूस को हरा देगी।
- ब्रिटेन यूक्रेन की मदद के लिए स्टॉर्मर बख्तरबंद वाहन भेजेगा। ये वाहन स्टारस्ट्रेक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस है।

लड़कियों से छिन जाएगा गर्भपात का अधिकार?

अमेरिका में पोलिटिको नाम के जर्नल ने अपनी रिपोर्ट से धमाका कर दिया। उसने दावा किया कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का ड्राफ्ट है जिसे औपचारिक तौर पर सुनाया जाना बाकी है। पोलिटिको के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर 1973 के ऐतिहासिक रो बनाम वेड फैसले को ह्यपलटनेह्ल जा रहा है। बेंच में जजों का बहुमत महिलाओं से गर्भपात का अधिकार छीने जाने के पक्ष में है। उस लैंडमार्क जजमेंट में कोर्ट ने अनचाहे गर्भ से छुटकारे को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताया था। पोलिटिको की रिपोर्ट के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में गर्भपात के अधिकार के समर्थक और एंटी-अबॉर्शन एक्टिविस्ट अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे।

रिपोर्ट

अगर जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का फैसला आता है तो अमेरिका में करीब 3.6 करोड़ महिलाओं से गर्भपात का अधिकार छिन जाएगा। तो आइए जानते हैं कि रो बनाम वेड फैसला आखिर था क्या, दुनिया के बाकी देशों में गर्भपात को लेकर क्या कानून हैं, भारत में गर्भपात को लेकर क्या नियम-कानून हैं, अपने देश की अदालतों ने इस मुद्दे पर कब-कब क्या अहम फैसले दिए।

अमेरिका में क्यों मचा है हंगामा

सबसे पहले बात करते हैं गर्भपात को लेकर अमेरिका में मचे हंगामे की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ड्राफ्ट ह्यलीकह्ल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है, ह्यये महिला का मौलिक अधिकार है कि वह तय कर सके कि वह अपने गर्भ का क्या करे ह्ल वैसे सुप्रीम कोर्ट अगर रो बनाम वेड फैसले को पलटता है तब भी अमेरिका के हर राज्य में गर्भपात एकदम से गैरकानूनी नहीं हो जाएगा। राज्यों को तय करना होगा कि वे गर्भपात को कानूनी बनाते हैं या गैरकानूनी। इस लिहाज से तो अमेरिकी महिलाओं को चिंता करने जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल, आशंका ये है कि अलबामा, जॉर्जिया, इंडियाना समेत अमेरिका के 24 राज्य गर्भपात को बैन करने वाले हैं। कोर्ट के फैसले के बाद वह तेजी से इस दिशा में बढ़ेंगे।

क्या है रो बनाम वेड फैसला

आखिर रो बनाम वेड का ऐतिहासिक फैसला है क्या, वह क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला नॉर्मा मैककॉर्वी नाम की एक महिला की याचिका पर आया था। अदालती कार्यवाही में उनको ही ह्यजेन रोह्ल नाम दिया गया है। दरअसल, मैककॉर्वी 1969 में अपना अबॉर्शन कराना चाहती थीं। उनके पहले से ही दो बच्चे थे। वह टेक्सस में रहती थीं जहां गर्भपात गैरकानूनी है, उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब प्रेग्नेंसी से मां की जान को खतरा हो। मैककॉर्वी ने फेडरल कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि टेक्सस का गर्भपात कानूनी असंवैधानिक है। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के तौर पर तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड का नाम था। जनवरी 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मैककॉर्वी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि गर्भ का क्या करना है, गर्भपात कराना है या नहीं, ये तय करना महिला का अधिकार है। जो बनाम वेड का ये फैसला ऐतिहासिक रहा जिसने अमेरिकी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया।

16 देशों में पूरी तरह बैन, 36 देशों में तभी जब गर्भ से मां की जान जा सकती हो

अगर जो बनाम वेड का फैसला पलटता है तो अमेरिका उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने हाल के समय में अबॉर्शन लॉ को बहुत सख्त किया है। 1994 के बाद से सिर्फ तीन देशों पोलैंड, अल सल्वाडोर और निकारगुआ ने ही गर्भपात कानूनों को सख्त किया है। मिस्र, इराक, फिलिपींस, लाओस, सेनेगल, निकारगुआ, अल सल्वाडोर, होंडुरास, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक समेत दुनिया में 16 देशों ने गर्भपात वर्जित है। 36 देश ऐसे हैं जहां गर्भपात वर्जित तो है लेकिन अगर मां की जान बचाने के लिए अगर अबॉर्शन जरूरी है तो उसकी इजाजत मिली हुई है।

भारत में गर्भपात को लेकर क्या है कानूनी स्थिति?

अब देखते हैं कि भारत में गर्भपात को लेकर क्या कानून हैं। यहां गर्भपात को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून रहा है। भारत में 51 साल से

अलग-अलग परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) ऐक्ट 1971 में पास हुआ। 2021 में इसमें संशोधन किया गया जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह (पांच महीने से बढ़ाकर छह महीने) कर दिया गया। संशोधित कानून के तहत रेप पीड़ित, कौटुंबिक व्यभिचार (नजदीकी रिश्तेदार द्वारा यौन उत्पीड़न) की शिकार या नाबालिग 24 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करा सकती हैं। इसके अलावा वे महिलाएं जिनकी वैवाहित स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो (विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो) और दिव्यांग महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन का अधिकार है। अगर भ्रूण में कोई ऐसी विकृति या गंभीर बीमारी हो जिससे उसकी जान को खतरा हो या फिर उसके जन्म लेने के बाद उसमें मानसिक या शारीरिक विकृति आने, गंभीर विकलांगता का शिकार होने का खतरा हो तब भी महिला को प्रेग्नेंसी के 24 हफ्ते के भीतर गर्भपात का अधिकार है।

महिला को क्यों होना चाहिए सुरक्षित गर्भपात का अधिकार?

महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार बहुत जरूरी है। इस दौरान महिला की प्राइवेसी का भी सम्मान किया जाना चाहिए। भारत की बात करें तो यहां गर्भपात का कानून भले ही बहुत प्रगतिशील हो लेकिन विवाह पूर्व सेक्स सामाजिक तौर पर वर्जित चीज है। अनचाहे गर्भ का क्या निदान है? अगर लिव इन में रह रही कोई महिला और पार्टनर अलग हो जाएं और उस दौरान महिला प्रेग्नेंट हो तो वह क्या करेगी? रेप की वजह से पीड़ित प्रेग्नेंट हो तो वह क्या करे? उन्हें गर्भपात का अधिकार तो होना ही चाहिए। भारत में महिलाओं को ये अधिकार है तब भी ज्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं कि अगर गर्भ 24 हफ्ते तक का हो तो अबॉर्शन कानूनी है। देश में इतना प्रगतिशील कानून होने के बावजूद असुरक्षित गर्भपात की वजह से तमाम महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु के लिए जिम्मेदार तीसरा प्रमुख कारण है।

प्रेग्नेंसी में भी दी अबॉर्शन की इजाजत

पिछले साल टीएमपी एक्ट में संशोधन से पहले विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को 20 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन का अधिकार था। 2021 में कानून में संशोधन के बाद अबॉर्शन के लिए प्रेग्नेंसी की अधिकतम समय सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में 20 हफ्ते से ऊपर, यहां तक कि 24 हफ्ते से भी ज्यादा लंबी प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन की इजाजत दी, कुछ भी मांग खारिज भी कर दी। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ फैसलों पर।

अदालतों में अक्सर आती हैं अबॉर्शन की मांग वाली याचिकाएं

हाई कोर्ट्स से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अक्सर गर्भपात की इजाजत को लेकर मामले आते रहते हैं। 20-24 हफ्ते से भी ज्यादा की प्रेग्नेंसी की वजह से ये मामले काफी जटिल भी होते हैं। कभी कोई रेप पीड़ित अबॉर्शन के लिए अदालत का रुख करती है तो कभी गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर बीमारी की वजह से कोर्ट से अबॉर्शन की इजाजत मांगी जाती है। महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले प्रतिज्ञा कैंपेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मई 2019 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक कुल 243 महिलाओं ने अबॉर्शन की मांग के लिए कोर्ट का रुख किया था। इनमें से 138 वयस्क महिलाएं थीं जबकि 105 नाबालिग थीं। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि कोर्ट मेडिकल बोर्ड गठित कर देता है जो तय करता है कि अबॉर्शन से कहीं महिला की जान जाने का खतरा तो नहीं है। ऐसे में कोर्ट 24 हफ्ते से ऊपर की प्रेग्नेंसी में भी अबॉर्शन की इजाजत दे देते हैं।

> एग फ्रीजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से गर्भधारण करने वाले अंडों को सुरक्षित रखा जा सकता है। आज के समय में कई ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो एग फ्रीज के माध्यम से अपने अंडों को सुरक्षित रख रहे हैं, इनमें राखी सावंत भी शामिल हैं।

राखी सावंत समेत कई सेलिब्रिटीज ने चुना

एग फ्रीज का रास्ता

कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने अपने एग फ्रीज करवा लिए हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं गर्भधारण करने वाले अंडों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज करवाती हैं। आज के समय में महिलाएं पेरेंट बनने से पहले अपने करियर को प्राथमिकता देती हैं, ऐसे में ज्यादा उम्र में पेरेंटहुड अपनाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आधुनिक तकनीक में एक फ्रीजिंग यानि Oocyte CryopreservÔtio»»f की मदद से अपने एग को फ्रिज किया जा सकता है।

क्या है एग फ्रीजिंग?

एग फ्रीजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं गर्भधारण करने वाले अंडों को

फ्रीज करवाती हैं और जब वे पूरी तरीके से प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती हैं तब अंडों को निकालकर संग्रहित किया जाता है और उन्हें पिघला कर एक प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है और भ्रूण को गर्भाशय में डाला जाता है।

क्यों जरूरी है एग फ्रीजिंग?

जन्म के बाद महिलाओं के अंडाशय की संख्या मिलियंस में होती है। लेकिन युवावस्था तक पहुंचते-पहुंचते यह संख्या आधी रह जाती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों में शुक्राणु हर दिन बनते हैं लेकिन महिलाओं में अंडे दोबारा नहीं बनते। उम्र बढ़ते ही अंडों की संख्या काफी कम हो जाती है। यही कारण होता है कि बाद में महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान परेशानी होती है। इसलिए इस समस्या को रोकने के लिए एग फ्रिज का सहारा लिया जाता है। इस प्रोसेस के माध्यम से अंडों को सुरक्षित रखते हैं, जिससे महिलाएं उन अंडों को बर्बाद होने से बचा सकें और बाद में उनका इस्तेमाल कर सकें।

एग प्रोसेस कब करवा सकते हैं?

- जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यदि आप अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहते हैं लेकिन आपको ये डर है कि आगे चलकर प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है तो ऐसे में आप एग फ्रीज करवा सकते हैं।
- यदि आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी है तो ऐसे में कीमोथेरेपी के कारण आपके अंडे खराब हो सकते हैं। ऐसे में आप एग फ्रीजिंग की मदद ले सकते हैं।
- यदि आप किसी और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तब भी आप अपने अंडों को बचाने के लिए एग फ्रीजिंग का सहारा ले सकती हैं।

रिलेशनशिप

झटके में टूट सकता है रिश्ता

जब आप लड़ाई से बचने के लिए अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं, तो मन ही मन घुटने लगते हैं। आप लड़ाई के डर से चाहकर भी पार्टनर से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं और फिर बाद में उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपको यह समझने होगा कि लड़ाई न हो, इसके लिए आपको उस वक्त माहौल के अनुसार शांत होने की जरूरत होती है, मगर बाद में आराम से पार्टनर तक अपने मन की बात जरूर करें। ऐसा करने से आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि पार्टनर से आप अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं।

प्यार से ज्यादा जगह दूरियां ले लेती हैं

जब आप सिर्फ लड़ाई-झगड़ों को इग्नोर करने के लिए पार्टनर के सामने अपनी बात रखने से बचने लगते हैं, तो आपके बीच कम्यूनिकेशन गैप बढ़ने लगता है। ऐसे में न सिर्फ आप बल्कि पार्टनर भी आपके मन की बात नहीं समझ पाता है। इससे प्यार का एहसास धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। लड़ाईयों से निजात पाने के लिए आप उस वक्त शांत हो सकते हैं या उसकी वजह को ढूंढकर उसे दोबारा न दोहराने की ठान सकते हैं, मगर बात न करना आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। दिल की बात ने कह पाने से रिश्ता में बढ़ती है बोरियतइस बात में कोई शक नहीं है कि जब आप अपने दिल की बात कहने से बचने लगते हैं, तो रिश्ते में दरार पैदा होने लगती है। लड़ाई न हो, इस डर से भले ही पार्टनर्स एक-दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर करने से बचते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके रिश्ते को बोरियत से भर देता है। उनके पास बात करने के लिए कुछ नया नहीं रह जाता। पार्टनर्स के बीच हेल्दी डिस्कशन का होना अच्छा माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं, उसे बात करके सुलझाएं, लेकिन मन की बात जरूर रखें।

दिखावेभरी जिंदगी अपनेपन को कर देती है खत्म

आप भले ही इस बात को सोचकर खुश हों कि आपकी पार्टनर से लड़ाई नहीं होती है, लेकिन आपको इसे भी समझना होगा कि ऐसे में आपके बीच दिखावेभरी जिंदगी जगह लेनी लगती है। जब हर दिन आप एक-दूसरे को प्यारी सी स्माइल देकर अपने मन की बात उन बातों को छिपाने लगते हैं, जिससे आपको लड़ाई का डर होता है, तो आपके रिश्ते में अपनापन खोने लगता है। ये आपके रिश्ते पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में आप पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को न्यूट्रल रखें और उन्हें अपनी बातों को प्यार से समझाएं।

“इस बात में कोई दोराय नहीं है कि हर कपल चाहता है कि उनके बीच लड़ाईयां न के बराबर हों, वह प्यार से एक-दूसरे के साथ रहें। लड़ाई-झगड़ों से बचने के लिए पार्टनर्स कई तरीके ट्राई करते हैं और अगर ऐसा होने लगता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि अगर आपकी अपने साथी से एकदम लड़ाई नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है और आगे चलकर आपके रिश्ते पर भारी पड़ सकती है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपकी पार्टनर से बुरी तरह से लड़ाई हो या फिर एक-दूसरे को बुरा भला कहने तक बात पहुंच जाए। लेकिन हेल्दी फाइट भी हर रिलेशनशिप के लिए जरूरी होती है, वरना आपके रिश्ते को दूसरे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।”

माह : मई 2022

राशिफल

मेष

मई का महीना कई राशि के जातकों के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छा रहने वाला है। इस महीने मेष मिथुन सहित कुछ और राशियों के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी। इस महीने किए गए निवेश भी काफी लाभ पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं इस पूरे महीने कैसी रहेगी मेष से मीन राशि तक सभी राशियों की आर्थिक स्थिति। इस महीने मेष राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। इसके लिए आपको किसी महिला की मदद मिल सकती है।

वृष

वृष राशि के लोग इस पूरे महीने अपने कामों में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। हालांकि, इस महीने आपके लिए उन्नति के मार्ग खुलते जाएंगे। इस महीने आर्थिक मामलों में आपके द्वारा किए गए लगातार प्रयास आपके लिए अंत में सफलता लेकर आ सकते हैं। इस महीने आपके द्वारा की गई यात्राओं से काफी सफलता मिलेगा। इस महीने सेहत को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

मिथुन

मई का यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में उन्नति वाला रहेगा। इस महीने की शुरूआत में आपको कुछ नए प्रोजेक्ट उत्साहित कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको आर्थिक उन्नति के शुभ अवसर दिलाएंगे। प्रेम संबंध में समय अनुकूल रहेगा। इस महीने आपकी सेहत में पहले से कहीं अधिक सुधार होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस महीने आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा।

कर्क

कर्क राशि के लोगों के लिए मई का महीना काफी अच्छा बीतने वाला है। इस महीने परिवार के पूरे सपोर्ट से जीवन में सफलता के मार्ग खुलेंगे। इस महीने आपकी सेहत में काफी सुधार नजर आएगा , तंदुरुस्ती बनेगी और मन प्रसन्न रहेगा। इस महीने की गई यात्राओं से भी अच्छी सफलता हासिल होगी। नौकरी पेशा जातकों को इस महीने कार्यक्षेत्र में थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। इस महीने आपके आर्थिक खर्च भी अधिक हो सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के लोगों के लिए यह महीने कई बदलाव लेकर आने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप इस वक्त नए प्रोजेक्ट की तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। इस महीने आपको अच्छा खासी मात्रा में धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी ये सम अनुकूल रहेगा। इस महीने एक नई शुरूआत जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनाएगी और परिवार में खुशियां लेकर आएगी। इस महीने सेहत थोड़ी नरम रह सकती है।

कन्या

कन्या राशि के लोगों के लिए मई का महीना आर्थिक सुधार वाला रहेगा। इस महीने आपको निवेशों द्वारा लाभ भी प्राप्त होगा। इस महीने हो सकता है की आप अपने कार्यक्षेत्र में किए गए वादों को पूरा न कर पाएं। इसलिए अगर आप बैकअप प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में भी सोच समझ कर निर्णय लें तो लाभदायक रहेगा। इस महीने की गई यात्राओं से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और करियर में सफलता मिलेगी।

तुला

तुला राशि के लोगों की इस महीने कार्यक्षेत्र में उन्नति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस महीने आप बड़े बुजुर्गों की मदद से सफलता हासिल कर सकते हैं। इस महीने आर्थिक तौर पर आपको धीरे-धीरे बदलाव नजर आएंगे। इस महीने आपको अपनी संतान को लेकर मन थोड़ा व्यथित हो सकता है। हो सकता है कि उनकी सेहत को लेकर भी आपकी चिंता अधिक बढ़ जाए। इस महीने जितनी यात्रा करेंगे तो अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के लोग इस महीने अपने परिवार के साथ सुखद और अच्छा समय बीताएंगे। इस महीने आप जितना पार्टी मूड में रहेंगे उतना अधिक सुकून प्राप्त होगा साथ ही आपकी सेहत में भी सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में किसी साझेदारी को लेकर मन चिंताओं से घिरा हो सकता है। आर्थिक मामलों में बंधन महसूस कर सकते हैं। इस माह यात्राओं को टाल दें तो बेहतर होगा। मई के आखिर में थोड़ा सा बेचैनी अधिक रहेगी और चिंता अधिक करेंगे।

धनु

धनु राशि के लोगों के लिए मई का महीना आर्थिक मामलों में लिहाज से यह महीना काफी अच्छा रहेगा। इस महीने आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस महीने आपके प्रेम संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप आपकी लाइफ में कष्ट लेकर आ सकता। अगर आप प्रोजेक्ट में ढिलाई भी हो सकती है।

मकर

मकर राशि के जातकों को इस महीने अपने परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही हो सकता है की आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बरती लापरवाही आपके प्रोजेक्ट में देरी लेकर आएगी साथ ही कष्ट बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में व्यय की स्थितियां प्रबल हो सकती हैं। घर परिवार में किसी युवा की सेहत को लेकर भी मन विचलित हो सकता है।

कुम्भ

कुंभ राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और इस संबंध में आपको किसी महिला की मदद प्राप्त हो सकती है। इस महीने आपको आर्थिक धन लाभ के योग हैं। इस महीने किए गए निवेशों से आपको काफी फायदा होगा। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। सेहत को लेकर थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। पूरे महीने आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए मई का महीना आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा। इस महीने किए गए निवेशों से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। सेहत के लिहाज से भी ये महीना अच्छा रहेगा। आपकी सेहत में काफी सुधार होगा। इस महीने की गई यात्राओं से विशेष सफलता के संयोग बन रहे हैं। साथ ही उन्नति भी मिलेगी। फिलहाल, आपको अपने कार्यक्षेत्र में तकलीफ उठानी पड़ सकती है।

RAMKRISHNA CARE

महानगरों जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एवं अनुभवी विशेषज्ञों की टीम.
अब रायपुर में.

रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, चिकित्सा क्षेत्र की जानी-मानी केयर ग्रुप श्रंखला का एक हिस्सा है. इसमें विभिन्न चिकित्सा विभागों के 100 से भी अधिक विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं. हम निरंतर चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने एवं इलाज को आधुनिक एवं उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत हैं.

359+ बेड्स हॉस्पिटल
100+ अनुभवी विशेषज्ञ
20+ सुपर स्पेशलिटी सर्विसेस
130+ आईसीयू बेड्स

श्रेष्ठता, विश्वसनीयता और भरोसे का प्रतीक
रामकृष्ण केयर अस्पताल
पचपेड़ीनाका, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)
• अपॉइंटमेंट : 07716165656 • इमरजेंसी के लिए : 1800 843 0000

'पवित्रेण पृथिवि मोत्पुनामि'

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः

छत्तीसगढ़िया संस्कृति हमर पहिचान ए
छत्तीसगढ़ महतारी के पावन माटी हमर अभिमान ए

हमर माटी तिहार

आस्था, परम्पराओं और संस्कृति की पुनर्स्थापना से
नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण

R.O NO.-12026/101